एक कम्युनिस्ट संगठन से आध्यात्मिक मठ की ओर

अक्टूबर 1995 से लेकर नवम्बर 1998 तक के तीन सालों के दौरान भारत की कम्युनिस्ट लीग (मा. ले) में गम्भीर विवाद पैदा हुआ। हमारा पार्टी संगठन इस विवाद को सकारात्मक दिशा में हल करके एक ज्यादा उच्च धरातल पर विचारधारात्मक, राजनीतिक, सांगठनिक एकता कायम करने में असफल रहा। इस विचारधारात्मक व राजनीतिक संघर्ष की दुःखद परिणति 15 नवम्बर '98 को एक पक्ष द्वारा 'सामान्य परिषद' (general council) के नेतृत्व में फूट का दस्तावेज जारी कर, कुत्सा प्रचार, तोड़–फोड़ की मुहिम प्रारम्भ करने के रूप में हुयी। यह पक्ष अगस्त '98 में विवाद को सुलझाने के लिए तयशुदा सम्मेलन का बहिष्कार कर पार्टी–संगठन की एकता को खंडित कर चुका था।

भारत की कम्युनिस्ट लीग (मा.ले.) अपनी स्थापना फरवरी, 1978 के बाद से '89 व '90–'91 में पहले ही दो बड़ी फूटों का शिकार हो चुकी थी। 1998 में तीसरी बड़ी फूट निश्चित तौर पर भारतीय कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आन्दोलन के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। टूट–बिखराव के दौर से गुजर रहे देश–दुनिया के कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए इस क्षति का महत्व इसलिए और भी ज्यादा है कि इससे भारतीय कम्युनिस्ट लीग (मा.ले.) द्वारा 1983 में सूत्रित भारतीय क्रांति की रणनीतिक लाइन (समाजवादी क्रांति) को कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आन्दोलन में स्थापित करने के प्रयासों को धक्का पहुंचा। भारतीय क्रांति को नव–जनवादी क्रांति की मंजिल में मानने वाले बिरादर संगठनों के साथ राजनीतिक वाद–विवाद चलाने और समाजवादी क्रांति की हमारी रणनीतिक लाइन के इर्द–गिर्द वर्ग–संश्रय का 'मॉडल' खड़ा करने की कोशिशें इस फूट से और ज्यादा कमजोर हुई हैं। हमारा यह दुःख और क्षोभ और ज्यादा बढ़ जाता है जब हमें दिखायी देता है कि दो–तीन वर्षों तक चले इस संघर्ष की अंतर्वस्तु ऐसी नहीं थी कि फूट (split) अपरिहार्य हो जाती। राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों का मूल्यांकन, कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आंदोलन के इतिहास का मूल्यांकन, विचारधारा जैसे बुनियादी महत्व के मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच मूलतः सहमति थी। विचारधारा–राजनीति के जो मतभेद मौजूद थे वे सम्मेलन में बहस–मुबाहिसे के जरिये हल किये जा सकते थे। अभी यह मतभेद रुझानों व प्रवृत्तियों से आगे बढ़कर सुस्पष्ट गैर क्रांतिकारी कार्यदिशा में परिवर्तित नहीं हुए थे।

खैर...आज छह वर्षों बाद हम इस विवाद और उसके अंजाम से उबरकर इंकलाब की जिम्मेदारियों के बोध को और ज्यादा गहरा कर अपनी क्षमताभर योगदान कर रहे हैं। 2002 में सम्मेलन आयोजित कर राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के अपने ज्यादा बेहतर मूल्यांकन के साथ हम '95 से '98 तक के संघर्ष के विभिन्न आयामों को जज्ब करके इसकी प्रासंगिकता को ज्यादा बेहतर ढंग से समझ सके हैं। उस समय के दोनों पक्षों की इन छह वर्षों की कार्यप्रणाली ने भी हमारी समझ को ज्यादा साफ किया है।

आज हम यह उचित समझते हैं कि कम्युनिस्ट क्रांतिकारी खेमे को १98 की फूट व उससे पूर्व चले अंतः पार्टी संघर्ष में दोनों पक्षों की अवस्थितियों से परिचित कराया जाय। 'लाल सलाम' के विभिन्न अंकों में हम इस विषय में अपनी सारगर्भित अवस्थिति पहले ही प्रस्तुत कर चुके हैं। जाहिर है कि इसे विस्तार से प्रस्तुत करने के पीछे यही मकसद है कि कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आन्दोलन के सभी घटक संगठन इस फूट के लिए जिम्मेदार अवस्थितियों के खिलाफ संघर्ष करें। इसके साथ यह भी कि इस फूट के लिए जिम्मेदार धड़ा तत्कालीन सामान्य परिषद,आज जिस मुकाम पर खड़ा हुआ है वह उसके और देश के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आन्दोलन के लिए सुखद नहीं है। इसकी वर्तमान स्थिति की आलोचना करना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। वैसे खुद सामान्य परिषद हमसे इस आलोचना की मांग करती रही है।

घटनाक्रम एक नजर में

• **अक्टूबर 1995** : तराई के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं (संघर्ष के दौरान एक पक्ष को इसी नाम से जाना गया) के साथ पार्टी संगठन के सचिव कामरेड रामनाथ की बैठक। इस बैठक को दोनों पक्ष विवाद की शुरूआत मानते हैं।

• **जुलाई 1996** : संगठन में पैदा हुये विवाद को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों में पार्टी सम्मेलन बुलाने के लिए सहमति।

• **नवम्बर 1996** : कांफ्रेंस तैयारी बैठक में (pre conference meeting) सम्मेलन की कार्यसूची निर्धारण हेतु दोनों पक्षों के द्वारा आलेखों का वितरण। कांफ्रेंस तैयारी बैठक में कांफ्रेंस की कार्यसूची निर्धारित।

• **जून 1997** : 28 सदस्योंका 10 दिवसीय **सम्मेलन**। (क) नेतृत्वकारी निकाय के तीन सदस्यों द्वारा व्यक्तिगत तौर पर, सचिव की पूर्ण सहमति प्राप्त राजनीतिक–सांगठनिक रिपोर्ट सम्मेलन में रखी गयी। (ख) केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट सम्मेलन में कमेटी द्वारा वापस ली गयी। (ग) विवाद के न सुलझने की स्थिति में सम्मेलन ने आगामी सम्मेलन का वर्ष व खाका तय किया। दोनों पक्षों के तीन–तीन सदस्यों को लेकर तालमेल कमेटी का गठन किया।आगामी सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी तराई के पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं को सौंपी गयी।

• **29 अप्रैल 1998** : तालमेल कमेटी की बैठक। आगामी सम्मेलन की प्रक्रिया व समय (6 से 10 सितम्बर '98) तय।

• **जून 1998** : केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी ने खुद को भंग करके एक ढीले–ढाले नेतृत्वकारी निकाय 'सामान्य परिषद' का गठन किया। (क) 'सामान्य परिषद' के पास केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के सभी अधिकार । (ख) 4 सदस्यीय पेशेवर कार्यकर्ताओं की के.सं.क. के बजाय यह 15 सदस्यीय पेशेवर कार्यकर्ताओं, सक्रिय कार्यकर्ताओं व शुभेच्छुओं का मंच था। सम्मेलन के 12 प्रतिनिधियों के अलावा इसमें तीन अन्य साथी शामिल किये गये, जिसमें एक के पास पार्टी सदस्यता भी नही थी। (ग) सामान्य परिषद न स्वयं पार्टी कमेटी थी न ही अन्य पार्टी कमेटियों को मान्यता देती थी। (घ) पूर्व सचिव रामनाथ सामान्य परिषद के सदस्य

नहीं थे। वे सामान्य परिषद के सलाहकार घोषित किये गये। जिनके पास पार्टी का हेडक्वार्टर रहेगा। जो आंदोलन में पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। जो पार्टी मुख–पत्र के संपादक होंगे। (ड.) सारे सदस्य, इकाइयां, निकाय, पार्टी संगठन से सम्बन्धित सारे व्यक्ति इसके अधीन घोषित किए गये। (च) सामान्य परिषद का कोई सचिव नहीं बल्कि तालमेलकर्ता (co-ordinator) नियुक्त किया गया। जून '98 की तालमेल कमेटी की बैठक में केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी द्वारा आपसी विश्वास बहाल करने के लिए लगातार बैठकों का प्रस्ताव। जिन बैठकों में केन्द्रीय महत्व के मुद्दों को रेखांकित करके परिधिगत मुद्दों को पहले ही हल किया जा सके।

- **6 से 8 सितम्बर '98** : तालमेल कमेटी द्वारा निर्धारित समय सारिणी के मुताबिक सम्मेलन सम्पन्न। (क) सामान्य परिषद द्वारा सम्मेलन का बहिष्कार किया गया। (ख) सम्मेलन ने भारत की कम्युनिस्ट लीग (मा.ले.) के पुनर्गठन का कार्यभार सामने रखते हुए नेतृत्वकारी निकाय के रूप में पुनर्गठन कमेटी का चुनाव किया।
- **13 सितम्बर** : पुनर्गठन कमेटी ने पार्टी की एकता बहाल करने की गरज से सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को सम्बोधित एक पत्र जारी किया। साथ ही जून '97 सम्मेलन के प्रतिनिधियों को सम्बोधित पत्र भी जारी किया।
- **15 नवम्बर 1998** : सामान्य परिषद ने फूट (split) की औपचारिक घोषणा करते हुए फूट का दस्तावेज जारी किया।

1995 में पैदा यह विवाद एक राजनीतिक विवाद था। हालांकि विवाद के एक पक्ष (केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी) ने 'एक व्यक्ति का अहंकार','महत्वाकांक्षा,' 'निराशा,' 'पलायन की प्रवृत्ति', 'असंतोष,' 'हठधार्मिता,' 'व्यक्तिगत कमजोरी' इत्यादि का गर्दो–गुबार खड़ा करके राजनीतिक संघर्ष से पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के इस संघर्ष को गैर राजनीतिक जामा पहनाने के प्रयासों के बावजूद अंततः केन्द्रीय व बुनियादी महत्व के राजनीतिक मुद्दे इस संघर्ष को अपनी आगोश में समेटते गये। शुरू–शुरू में यह विवाद सांगठनिक कार्यशैली तथा कुछ राजनीतिक मुद्दों पर मतभेद के रूप में सामने आया था। 1995 से '98 के तीन वर्षों के संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों की अवस्थितियां व क्रियाकलाप ज्यादा मुखर होकर कई राजनीतिक मुद्दों को इसमें जोड़ते चले गये। अतः केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी ने इसे आगे चलकर एक राजनीतिक संघर्ष माना और सामान्य परिषद ने नवम्बर '98 में जारी फूट के दस्तावेज में इसे ओछी महत्वाकांक्षाओं व अहंकार से संचालित दो लाइनों का संघर्ष कहा। संघर्ष के प्रारम्भ में केन्द्रीय दिखायी देने वाली चीजों को उन्होंने इस दस्तावेज में महज विश्लेषण तक सीमित कर दिया।

इन तीन वर्षों के राजनीतिक संघर्ष के दौरान हमने मुख्यतः चार स्रोतों; (1) केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के साथियों और हमारे बीच हुई आमने–सामने की बातचीत, (2) उनके द्वारा लिखे गये पत्र, (3) पार्टी संगठन के दस्तावेज, (4) केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी द्वारा जारी प्राधिकृत आडियो कैसेट,का ही इस्तेमाल किया था, उन्हीं को आधार बना कर हम आन्दोलन के समक्ष भी अपनी अवस्थिति रख रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष के तौर पर आज भूतपूर्व केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी व वर्तमान में सामान्य परिषद विकसित

होकर जहां पहुंचे हैं इसका जायजा लेने के लिए हमारे एकता प्रस्ताव के जवाब में लिखे गये पत्रों व दो दिवसीय वार्ता को भी हम आधार बनायेंगे।

विचारधारात्मक संघर्ष के मुद्दे

1995.96 में जब इस संघर्ष की शुरूआत ही हुयी थी तब तक यह विवाद मुख्यतः सांगठनिक लाइन व कार्यशैली पर केन्द्रित था। जैसे–जैसे संघर्ष विकसित हुआ विचारधारा से केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी का विचलन सुस्पष्ट होता चला गया। 1997 की गर्मियों में लाल तारा–4 (राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मूल्यांकन सम्बन्धी दस्तावेज) तैयार करने के लिये सचिव का. रामनाथ द्वारा दिये गये वक्तव्यों की सम्पादित (edited) आडियो कैसेट्स के जारी होने के साथ ही विचारधारात्मक विचलन की अभिव्यक्तियां हमारे सामने आयीं। यहां यह गौरतलब है कि 4.7 जुलाई 1998 की तालमेल कमेटी की बैठक में केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के सदस्यों ने पुनः यह सूचना दी कि ये कैसेट्स आधिकारिक हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन पर टिप्पणी करते हुए का. रामनाथ माओ द्वारा 1956 से 1963 के बीच चलायी गयी बहस को '63 तक अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन के लिए न खोलने को, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की गम्भीर गलती मानते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा ख्रुश्चेवी संशोधनवाद के खिलाफ चलायी गयी बहस पर की गयी यह टिप्पणी सीधे–सीधे 'महान बहस' की पहली टिप्पणी को अस्वीकार करना है। का. रामनाथ का मानना है कि ख्रुश्चेवी संशोधनवाद के खिलाफ खुले संघर्ष को माओ ने सात साल तक रोके रखा और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन का गम्भीर नुकसान किया। उनके अनुसार 'महान बहस' को 1963 के बजाय 1956 में ही शुरू करके समाजवादी खेमे में विभाजन को अंजाम दे देना चाहिये था।

हमारा मानना है कि 1956–63 के बीच चलायी गयी बहस के बारे में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राय ठीक है। इस राय से भारत के कम्युनिस्ट क्रांतिकारी आन्दोलन की सहमति हमारी विचारधारात्मक दृढ़ता और वस्तुगत परिस्थितियों के मद्देनजर 'एकता–संघर्ष–एकता' के सही मार्क्सवादी सिद्धान्त के आत्मसातीकरण की अभिव्यक्ति है।

1956 से श्63 तक का काल लम्बे व निर्णायक संघर्ष में सर्वहारा की एकता को बनाये रखने के लिए किया जाने वाला आवश्यक उसूली समझौता है। अगर माओ व चीनी कम्युनिस्ट पार्टी इस निर्णायक संघर्ष को धैर्यपूर्वक संचालित न करती तो 1956 में न सिर्फ समाजवादी खेमा फूट का शिकार हो जाता बल्कि चीनी क्रांति में भी 1956 के बाद से ही ल्यू शाओ–ची का धड़ा ख्रुश्चेव के साथ खुले तौर पर खड़ा होकर चीन के भविष्य को पूंजीवादी दिशा में ले जा सकता था। 1956 में सी.पी.एस.यू. की बीसवीं कांग्रेस में जब ख्रुश्चेव की संशोधनवादी लाइन सामने आयी तभी सी.पी.सी की आठवीं कांग्रेस में भी ल्यू शाओ–ची की लाइन हावी थी। ऐसे में माओ ने एक ओर ख्रुश्चेव की संशोधनवादी लाइन के खुलकर सामने आने के बाद तक धैर्यपूर्वक संघर्ष चलाया बल्कि दूसरी ओर चीन में समाजवादी शिक्षा अभियान, "सौ फूलों को खिलने दो" व "महान अग्रवर्ती छलांग" का कार्यक्रम लागू कर दक्षिणपंथियों के भौतिक आधार को कमजोर किया।

इस तरह 1961में सी.पी.एस.यू. की 22वीं कांग्रेस द्वारा पार्टी को "समस्त जनता की पार्टी" और सोवियत राजसत्ता को "समस्त जनता का राज्य" घोषित करने और '62–'63 में समाजवाद का आधार मजबूत होने की माकूल वस्तुगत स्थितियों में ही माओ 'महान–बहस' की शुरूआत कर सकते थे। एकता को बनाये रखते हुए संघर्ष कर गलत लाइन को अलगाव में डालने व बेपर्दा करने के लिए प्रतिकूल राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में माओ द्वारा चलाया गया संघर्ष बेमिसाल है।

जून, 1997 सम्मेलन की समाप्ति के अगले दिन 29 जून को का. रामनाथ ने माओ के मूल्यांकन को आगे बढ़ाते हुए 'महान–बहस' चलाने में की गयी 7 सालों की देरी के कारण माओ की मनोगत कमजोरियों में तलाशे। उन्होंने कहा कि एशियाई होने की वजह से माओ हमारी–आपकी तरह ही कमजोर मानसिक बनावट के आदमी थे। इसी वजह से वे सात वर्षों तक साहस के बजाय भीरूता का परिचय देते रहे। विश्लेषण की इस अधिभूतवादी प्रणाली को हम अस्वीकार करते हैं। राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय वर्ग–संघर्ष की स्थिति, कम्युनिस्ट पार्टियों की स्थिति व रणकौशल का जायजा लेने के बजाय माओ की मनोगत स्थिति का आध्यात्मिक मूल्यांकन करने का दुस्साहस हम ठीक नहीं मानते। विश्लेषण की इस व्यक्ति केन्द्रित आध्यात्मिक प्रणाली के दर्शन, हमें आगे भी पार्टी–निर्माण सम्बन्धी रामनाथ व केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी की चिंतन प्रणाली में मिलेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आंदोलन के अपने मूल्यांकन में वे स्टालिन को भी नहीं बख्शते। उनका मानना है कि स्तालिन तीसरे इंटरनेशनल के माध्यम से सी.पी.एस.यू. की आंतरिक समस्याओं को दुनिया की शेष पार्टियों की भी आंतरिक समस्या बना देते हैं। सोवियत पार्टी में त्रात्स्कीवाद के खिलाफ संघर्ष चलाने पर अगर दुनिया की अन्य पार्टियों में भी संघर्ष चला तो इसे रामनाथ गलत मानते हैं। वे इसके लिए स्तालिन को दोषी मानते हैं।

हमारा मानना है कि उस समय दुनिया की सबसे अनुभवी व विकसित कम्युनिस्ट पार्टी में अगर किसी गलत लाइन के खिलाफ संघर्ष चल रहा है और उससे सबक लेकर दूसरी पार्टियां भी अपने भीतर त्रात्स्कीवाद की गलत प्रवृत्तियों व रुझानों के खिलाफ संघर्ष चलाती हैं तो यह कहीं से भी गलत नहीं है। और फिर इस सबमें स्तालिन कहां गलत हैं, यह समझना और भी ज्यादा मुश्किल है।

का. रामनाथ सी.पी.सी. पर अपनी टिप्पणी में कहते हैं कि वह इंटरनेशनल बनाने की जरूरत नहीं समझती थी। हम समझते हैं कि यह मूल्यांकन सी.पी.सी. के अंतर्राष्ट्रवाद पर हमले के अलावा और कुछ भी नहीं है। एक बेबुनियाद हमला।

सी.पी.सी. और इंटरनेशनल का मूल्यांकन करते समय द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान की परिस्थितियों व 1943 में तीसरे इंटरनेशल को भंग करने के दौरान की परिस्थितियों का लेखा–जोखा जरूरी है। ऐसा करके कोई वस्तुगत मूल्यांकन प्रस्तुत करने के बजाय कामरेड रामनाथ मुक्त चिंतन की उड़ान भरते हुए आगे फरमाते हैं कि तीसरे इंटरनेशनल में कुछ लोग स्तालिन के प्रति एलर्जिक (allergic) थे। संदर्भ साफ है, सी.पी.सी. और माओ स्तालिन के प्रति एलर्जिक थे। रामनाथ इस एलर्जी को तीसरे इंटरनेशनल के टूटने की वजह बताते हैं। तीसरे इंटरनेशनल के भंग होने के कारण वस्तुगत परिस्थितियों में तलाशने के बजाय व्यक्तिगत पसंदगी–नापसंदगी, विद्वेषों, एलर्जी में तलाशने की यह प्रणाली भाववाद के अलावा और क्या है

1943 में कोमिन्टर्न को भंग करने के लिए पेश किये गये अपने प्रस्ताव में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की इक्जीक्यूटिव कमेटी के प्रीसिडियम ने कहा,

> "जैसे–जैसे विभिन्न देशों की आंतरिक और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां जटिलतर होती गई, किसी अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र के माध्यम से प्रत्येक देश के मजदूर आंदोलन की समस्याओं का समाधान उतना ही अनुल्लंघनीय बाधाओं से ग्रस्त होता गया। घटनाओं ने यह दिखाया कि यह प्रस्ताव वास्तविकता के अनुकूल था और सही था।" (`VII th Comment',`The Great Debate', Sarvahara Prakashan,1986, page 259, अनुवाद हमारा)

हम 'महान–बहस' की सातवीं टिप्पणी को सही मानते हुए 1943 में तीसरे इंटरनेशनल को भंग किये जाने को गलत नहीं मानते।

तीसरे इंटरनेशनल के बारे में का.रामनाथ एक अन्य मनोगतवादी मूल्यांकन रखते हैं। उनका मानना है कि औपनिवेशिक देश की कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा उपनिवेश की कम्युनिस्ट पार्टी का मार्गदर्शन करने का फैसला एक गलत फैसला था क्योंकि अपने राष्ट्रीय हितों की वजह से वह उपनिवेश की पार्टी को सही मार्गदर्शन दे ही नहीं सकती थी।

यह मूल्यांकन सर्वहारा अंतर्राष्ट्रवाद पर जारी फतवे के अलावा कुछ नहीं है। हमारा मानना है कि इंटरनेशनल का मूल निर्णय ठीक था। इंटरनेशनल की परिपक्व पार्टियों में औपनिवेशिक देशों की पार्टियां ही अपने शासक वर्ग के उपनिवेशों के हालातों की सबसे बेहतर जानकारी दे सकती थी। औपनिवेशिक देशों की कम्युनिस्ट पार्टियां अपने मुल्क के शासकों से उतनी ही नफरत करती थी जितना कि उपनिवेशों की आम जनता व कम्युनिस्ट पार्टियां। मात्र औपनिवेशिक देशों में पैदा होने की वजह से उन पर त्रात्स्कीपंथियों की तरह राष्ट्रवादी भटकावों का आरोप लगा देना गलत है।

अपने एक अन्य वक्तव्य में का.रामनाथ 1967 के नक्सलबाड़ी उभार के बाद सी.पी.सी. द्वारा भारत को अर्द्ध–सामंती, अर्द्ध–औपनिवेशिक बताने की कार्यवाही को गलत बताते हैं। उनके अनुसार इससे भारत के कम्युनिस्ट आंदोलन में चल रही अर्द्ध–उपनिवेश, नव उपनिवेश की बहस खत्म हो गयी। वे इसे बिना किसी जिम्मेदारी के पूर्ण अधिकार (full right with no responsibilities) की स्थिति बताते हैं।

सी.पी.सी. ने भारत के कम्युनिस्टों को साफ बताया था कि उनके चेयरमैन भारतीय कम्युनिस्टों के चेयरमैन नहीं हैं। सी.पी.सी. कभी भी भारत के कम्युनिस्टों की औपचारिक सलाहकार नहीं बनी। इस तरह सी.पी.सी. के पास कोई अधिकार नहीं थे बल्कि वह अपने अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भारतीय कम्युनिस्टों को राय–मशविरा जरूर देती थी। किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी से उसका यह अधिकार नहीं छीना जा सकता कि वह देश–दुनिया की घटनाओं व अलग–अलग समाजों की स्थिति का मूल्यांकन करे। अर्द्ध–सामंती, अर्द्ध–औपनिवेशिक सूत्रीकरण को वेदवाक्य मानकर अगर हम आपस में बहस बंद कर देते हैं तो इसके लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा की गयी टिप्पणियां कहीं से भी जिम्मेदार नहीं हैं।

का. रामनाथ अपने वक्तव्यों में लेनिन की साम्राज्यवाद की थीसिस की भी गलत व्याख्या करते हैं। उनका कहना है कि साम्राज्यवादी अपने देश के सर्वहारा को घूस देता है परन्तु सर्वहारा इसे घूस नहीं

अपना हक समझकर लेता है। ऐसी व्याख्या लेनिन की थीसिस में मौजूद साम्राज्यवाद के सामाजिक अवलम्ब की अवधारणा को नकारती है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद अतिलाभ में से एक हिस्सा घूस के तौर पर देकर मजदूर नेताओं और अभिजात मजदूरों के ऊपरी हिस्से को अपनी ओर कर लेता है। 'अभिजात मजदूरों' का यह स्तर सर्वहारा विश्व दृष्टिकोण को त्यागकर पूंजीपति वर्ग का असली दलाल, गुर्गा व सुधारवाद, अंधराष्ट्रवाद का असली वाहक और उसका सामाजिक आधार बना हुआ है।

इसी तरह 'विकसित देशों में ऊर्जा भंडारों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, समाजवाद के आने पर आज के स्तर का ऊर्जा व्यय नहीं होगा, ऐसा करने पर धरती मिट जाएगी', जैसी पर्यावरणवादी अवस्थिति भी कामरेड अपने वक्तव्य में रखते हैं।

'लाल तारा–4' के लिए का. रामनाथ एक गलत प्रस्थापना यह भी देते हैं कि पूंजीवाद में सेवा क्षेत्र के विस्तार की असीम सम्भावनायें हैं। अपनी बात की पुष्टि के लिए वे एक अमीर सनकी का उदाहरण देते हैं जिसने अपनी बिल्लियों के लिए सैकड़ों कमरों का पांच सितारा होटल बनवा डाला।

हम इस बात को गलत मानते हैं। मार्क्सवादी अर्थशास्त्र बताता है कि पूंजीवाद में अन्य क्षेत्रों की तरह ही सेवाक्षेत्र का विस्तार भी पूंजी और बाजार की उपलब्धता पर निर्भर करता है। आज पूंजी के अतिसंचय की वजह बाजार की कमी से पैदा हुई निवेश की दिक्कतें ही हैं। न तो पूंजीपति वर्ग खुद सारा बाजार बन सकते हैं और न ही सनकी पूंजीपति सेवा क्षेत्र के असीम विस्तार की सम्भावना पैदा करते हैं।

इस तरह का.रामनाथ और केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी ने इन गम्भीर विचारधारात्मक विच्युतियों व भटकावों का प्रतिनिधित्व किया। आज भी रामनाथ व सामान्य परिषद अपनी उन अवस्थितियों में डटी हुई है। 1998 के बाद आज तक उन्होंने अपनी अवस्थितियों पर कोई लिखित दस्तावेज जारी नहीं किया है। इसलिए हमें यह कहने में जरा मुश्किल है कि विचारधारात्मक भटकाव की यह यात्रा आज कहां पहुंच चुकी है। हालांकि 'महान बहस' की भूमिका (1998 हिन्दी संस्करण, अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशनद्ध उन्होंने 1957 और 1960 में माओ व चीनी पार्टी द्वारा किये गये समझौतों को गैर उसूली करार दिया है। अगस्त 2002 में हमारे द्वारा भेजे गये एकता प्रस्ताव पर हुई इकलौती वार्ता में उन्होंने 1997 के आडियो कैसेट्स की अवस्थितियों को अपनी चिन्तन प्रक्रिया और 'महान बहस' (1998 हिन्दी संस्करण, अन्तर्राष्ट्रीय प्रकाशन) की भूमिका' को अपनी आधिकारिक अवस्थिति बताया है। इससे जाहिर होता है कि उनकी चिंतन प्रक्रिया इन विचारधारात्मक विच्युतियों को और आगे बढ़ाने की ही दिशा में है। इस पूरे संघर्ष के दौरान रामनाथ व केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के सदस्यों की चिंतन प्रक्रिया कम्युनिस्टों के बजाय स्वच्छंद–बुद्धिजीवियों की रही है और जारी है।

रणनीतिक दिशा पर संघर्ष के बिन्दु

1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में आये बदलावों की चर्चा करते हुए का.रामनाथ कहते है कि तीसरी दुनिया का शासक वर्ग साम्राज्यवाद का एजेंट हो जायेगा। दूसरी तरफ वे यह भी कहते हैं कि वह अपनी राजनीतिक आजादी नहीं खोयेगा।

हमारा कहना है कि यह एक विसंगतिपूर्ण अवस्थिति है। इस अवस्थिति के मुताबिक तीसरी दुनिया के शासक वर्ग अपनी आजादी खो देंगे। इनका अस्तित्व साम्राज्यवाद पर निर्भर हो जायेगा। इस तरह आर्थिक तौर पर तीसरी दुनिया के देश नव–उपनिवेश बन जायेंगे जबकि राजनीतिक तौर पर नहीं। यह अवस्थिति 1987 के पार्टी सम्मेलन द्वारा मान्य अवस्थिति के उलट है। 1987 के दस्तावेज में दर्ज भारतीय पूंजीपति वर्ग को साम्राज्यवाद का कनिष्ठ साझेदार (junior partner) बताने वाली अवस्थिति को भी गलत बताते हुए का.रामनाथ कहते हैं कि भारत का शासक वर्ग साम्राज्यवाद का एजेंट है, संश्रयकारी (collaborationist) है। यह वक्तव्य तब और हास्यास्पद हो जाता है जब वे कहते हैं कि वह तो कभी भी उसे कनिष्ठ साझेदार नहीं कहते रहे हैं।

आज सामान्य परिषद 1987 की अवस्थिति को छोड़कर संश्रयकारी के सूत्र को अपना चुकी है। हालांकि 1987 के सम्मेलन द्वारा तय कनिष्ठ साझेदार सूत्रीकरण के बदलने की जानकारी उन्होंने आन्दोलन को नहीं दी है और न ही इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है। 1995.98 के अंतः पार्टी संघर्ष के दौरान आडियो कैसेट्स में ही का.रामनाथ द्वारा छोटे कारखानेदार और धनी किसानों के भी साम्राज्यवादी दबाव की वजह से क्रांति के पक्ष में आ खड़े होने की संभावना देखना भी, संघर्ष का मुद्दा रहा है।

इस तरह भारतीय पूंजीपति वर्ग को संश्रयकारी बताने व क्रांति में छोटे कारखानेदार और धनी किसान की भूमिका की स्वीकारोक्ति ने का. रामनाथ को नव जनवादी क्रांति की रणनीतिक लाइन के ज्यादा करीब खड़ा कर दिया है।

आज सामान्य परिषद की गैर पार्टी रचनाओं में नेहरू मॉडल के टूटने का मातम मनाने और साम्राज्यवादी दबाव को बढ़ा–चढ़ा कर देखने की प्रवृत्ति दिखायी देती है। इन रचनाओं में श्91 के बाद की परिघटनाओं का ठीक ढंग से विश्लेषण न कर पाने की वजह से संश्रयकारी, एजेंट, दलाल जैसे सूत्रीकरण और तीसरी दुनिया के पुनर्उपनिवेशीकरण की भविष्यवाणियां दिखायी देती हैं। भारत का शासक वर्ग साम्राज्यवाद का कनिष्ठ साझेदार है। साम्राज्यवाद के साथ गठजोड़ में इसकी स्थिति हाल–फिलहाल अधीनता की है। इस बारे में अपनी विस्तृत राय 15.21 जून 2002 के बीच सम्पन्न हुयी पांचवीं कांफ्रेंस के दस्तावेजों में हम रख चुके हैं।

पार्टी निर्माण सम्बन्धी मतभेद के बिन्दु

तीन सालों से ज्यादा चले इस संघर्ष के दौरान इस बात पर दोनों पक्ष सहमत थे कि क्रांति करने के लिए एक क्रांतिकारी कम्युनिस्ट पार्टी की जरूरत है। इस बात पर भी सहमति थी कि क्रांतिकारी पार्टी का गठन व निर्माण ही आज हमारा केन्द्रीय कार्यभार है तथा ऐसी पार्टी के निर्माण के लिए क्षमताभर योगदान हेतु अपने पूर्व पार्टी संगठन की राजनीतिक–सांगठनिक गतिविधियों को और ज्यादा ठोस रूप देते हुए कम्युनिस्टों की एक कोर का निर्माण किया जाय।

कम्युनिस्टों की कोर का निर्माण करने के लिए क्या तौर–तरीके अख्तियार किये जायें, इस पर मतभेद थे। इन मतभेदों का दायरा पार्टी निर्माण के अनेकानेक बिन्दुओं को अपने आगोश में समेटे हुए था।

1. पार्टी इतिहास का सार–संकलनः एक भाववादी विश्लेषण पद्धति

विचारधारात्मक मतभेदों की तथा अन्तर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट आन्दोलन – खास तौर से स्तालिन व माओ का मूल्यांकन करते समय का. रामनाथ के नेतृत्व में केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी ने वस्तुगत परिस्थितियो को नजरअंदाज करके जो भाववादी व्यक्तिकेन्द्रित विश्लेषण पद्धति अपनायी थी, उसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं। परिस्थितियों, विषयवस्तु और सामाजिक, ऐतिहासिक व विचारधारात्मक जड़ों पर बल देने के बजाय व्यक्तियों को जिम्मेदार मानने की विश्लेषण पद्धति का. रामनाथ की पार्टी कार्यशैली व पार्टी निर्माण सम्बन्धी पहुंच का प्रमुख अवयव रही है।

जून श्97 के पार्टी सम्मेलन में केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी द्वारा पार्टी इतिहास का सार– संकलन करते हुए मौजूदा विवाद का विश्लेषण करते हुए "राजनीतिक–सांगठनिक रिपोर्ट" प्रस्तुत की गयी थी। "यह पार्टी सचिव द्वारा प्रस्तुत नहीं है" यह रिपोर्ट का उपशीर्षक था। पूरी रिपोर्ट में रामनाथ के अलावा तात्कालिक नेतृत्व के व्यक्तियों, उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि, गलतियों, कमियों बुराइयों को हमारे पार्टी संगठन के ठहराव के लिए जिम्मेदार बताया गया। पूर्व में हुयी फूटों, व्यक्तियों के इंकलाब से पीछे हट जाने व तात्कालिक विवाद के लिए भी कुछ व्यक्तियों की ओछी महत्वाकांक्षाओं, गलीज पारिवारिक पृष्ठभूमि को ही जिम्मेदार ठहराया गया था।

पूरी रिपोर्ट में वस्तुगत परिस्थितियों, देश–दुनिया के कम्युनिस्ट आन्दोलन,हमारे पार्टी संगठन की स्थितियों में व्यक्तियों को अवस्थित कर देखने का नजरिया गायब था।

अंततः पूरे इतिहास व मौजूदा विवाद को हल करने के लिए इस रिपोर्ट से सिर्फ यही निष्कर्ष निकलता था कि व्यक्ति ठीक हों। जाहिर है व्यक्तियों के कम्युनिस्ट रूपान्तरण के लिए समूची पार्टी के बोल्शेविकीकरण का भी कोई कार्यभार इससे नहीं निकलता था। पार्टी निर्माण के विविध आयामों से इस पूरी रिपोर्ट का कोई लेना–देना नहीं था। विश्लेषण की द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पद्धति का पूर्ण निषेध करती इस भाववादी रिपोर्ट को सम्मेलन द्वारा स्वीकार नहीं किया गया।

इस पूरे संघर्ष के दौरान हमारा मानना है कि पार्टी को व्यक्तियों के संग्रह के रूप में देखने के बजाय एक जैविक इकाई (organic whole) के रूप में देखा जाना चाहिए। व्यक्तियों को समूह से अलग–थलग विच्छिन्न करके उनका मूल्यांकन करने के बजाय समूची पार्टी के साथ व्यक्ति को निश्चित,गतिमान रिश्तों में देखना चाहिए। समस्या के कारण व्यक्ति में ढूंढ़ने के बजाय समूची पार्टी (और वह परिवेश जिसमें पार्टी काम कर रही होती है) से प्रस्थान करके ही व्यक्ति तक पहुंचने की पद्धति का इस्तेमाल किया जाना चाहिये। कार्यकर्ताओं के क्रांतिकारी रूपान्तरण के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिये। मात्र आलोचना–आत्मालोचना की पद्धति पर अमल करके व्यक्ति विशेष खुद अपनी विजातीय प्रवृत्तियों से लड़कर मुक्त नहीं हो सकता बल्कि वर्ग–संघर्षों में तपकर समूची पार्टी के रूपान्तरण से ही व्यक्ति के रूपान्तरण का सवाल जुड़ा हुआ है। बेशक, आलोचना–आत्मालोचना व्यक्ति के रूपान्तरण में महत्वपूर्ण अवयव हैं।

द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी पद्धति पर अमल करके ही हम पार्टी इतिहास का सही सार–संकलन कर सकते हैं। मौजूदा विवाद को समझ सकते हैं। समूची पार्टी व व्यक्तियों के कम्युनिस्ट रूपान्तरण की दिशा में बढ़ सकते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी के निर्माण के लिए ठोस व्यवहारिक कार्यभार निकाल सकते हैं।

पार्टी निर्माण के इस संघटक तत्व, जो कि मतभेदों के मूल में बना हुआ था, से गहरे रूप से अंतर्सम्बद्ध अन्य तत्वों पर मतभेद निम्न थे।

2. औपचारिक जन–संगठनों का निर्माण:

केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के साथी औपचारिक जनसंगठनों का निर्माण करने व उन्हें विकसित करने के प्रति गम्भीर नहीं थे। संघर्ष के शुरूआती चरण में उन्होंने जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए औपचारिक जन–संगठनों के निर्माण की हमारी नीति की मुखालफत करते हुए हम पर जनतावादी भटकाव तथा जन–पार्टी बनाने के आरोप भी लगाये। हालांकि संघर्ष के आगे बढ़ने पर केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी ने पिछले दरवाजे से ये आरोप तो वापस ले लिये परन्तु एक ढीले–ढाले अंतर्वर्गीय–अंतर्तबकायी मंच को औपचारिक जनसंगठन बनाने के हमारे प्रयासों का वे अन्त तक विरोध करते रहे।

हमारा मानना है कि आदर्श कम्युनिस्ट कोर के इंतजार में अपने जनकार्यों को औपचारिक रूप न देना गलत है। बल्कि एक हद तक पार्टी कतारों के विकसित हो जाने के बाद अनौपचारिकता की यह स्थिति उनके आगे के क्रांतिकारी रूपान्तरण में बाधा ही पहुंचाती है।

3. पार्टी का लेनिनवादी ढांचा:

जनवादी–केन्द्रीयता के उसूल पर औपचारिक ढांचा खड़ा करने के प्रति केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के साथियों की पहुंच गम्भीर नहीं रही है। सचिव का. रामनाथ तो इस मामले में दो हाथ आगे जाकर मौजूद औपचारिक ढांचे का खुलेआम उल्लंघन तक करते थे। 1997 के जिन व्याख्यानों के आडियो कैसेट्स का जिक्र हम पहले कर चुके हैं, उन व्याख्यानों में का. रामनाथ ने गैर–पार्टी सदस्यों तक के समक्ष विचारधारा, रणनीति के मुद्दों पर ढीले–ढाले बयान दिये थे।

1992 के बाद से ही पार्टी मुख–पत्र तो दूर, कोई पार्टी सर्कुलर तक जारी नहीं किया गया। पार्टी ढ़ाचे के नाम पर केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के अलावा समूची पार्टी का सुगठित–सुव्यवस्थित ढांचा बनाने के प्रयास तक नहीं किए गये।

पार्टी ढांचे में कमेटी व्यवस्था के प्रति अपने नकारात्मक रुख को आगे बढ़ाते हुए और का. रामनाथ की स्वेच्छाचारी, बुद्धिजीवी मार्का कार्यशैली को संस्थागत करते हुए केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी की जगह सामान्य परिषद–सलाहकार रूप को जून, 1998 में अपनाया गया।

हमारा मानना है कि इस नजरिये से पार्टी गठन, पार्टी निर्माण की दिशा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा जा सकता।

4. पार्टी में स्वेच्छाचारी कार्यशैली:

पार्टी की जनता के प्रति जवाबदेही, कमेटियों के मार्फत सभी पार्टी सदस्यों की समूची पार्टी के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के बजाय का. रामनाथ व केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के साथी स्वेच्छाचारिता के पक्षधर रहे हैं।

संघर्ष के दौरान कार्यसूची व तारीखों में लगातार किन्तु–परंतु के साथ फेरबदल , अंततः तयशुदा सम्मेलन का बहिष्कार इस कार्यशैली की मुखर अभिव्यक्तियां रहीं।

फूट के बाद

जैसा कि स्वाभाविक ही है; 1995 में सांगठनिक कार्यशैली और राजनीतिक अवधारणाओं की गलत प्रवृत्तियों व रूझानों के खिलाफ शुरू हुआ यह संघर्ष 1998 आते–आते दो लाइनों के संघर्ष में तबदील हो गया। समय–समय पर नये–नये राजनीतिक मुद्दे इसमें जुड़ते चले गये। संघर्ष के आगे बढ़ने पर दोनों पक्षों की राजनीतिक प्रवृत्तियों, रुझानों का ज्यादा मुखर होते जाना लाजमी है।

इस संघर्ष का सकारात्मक पक्ष यह रहा कि दो–तीन सालों तक कई उतार–चढ़ावों के साथ दोनों पक्षों के बीच कई दस्तावेजों के आदान–प्रदान के जरिये यह संघर्ष संचालित हुआ। पार्टी–संगठन के अच्छे–खासे हिस्से को इसने अपने आगोश में लिया। नकारात्मक यह कि गैर जरूरी तरीके से संघर्ष के एक पक्ष – केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी व का.रामनाथ ने जून, 1998 में पेशेवर क्रांतिकारियों के शीर्ष निकाय को भंग करके अपने पक्ष में गुट बनाने की कार्रवाई की और अंततः इसको अंजाम तक पहुंचाकर '98 सम्मेलन का बहिष्कार किया।

अतः पार्टी संघर्ष से मुंह चुराकर भाग खड़े होने की वजह से पार्टी संगठन के कम्युनिस्ट रूपांतरण व ठहराव तोड़ने के सवाल से आज भी सामान्य–परिषद के साथी उसी जगह पर कदमताल करते हुए जूझ रहे हैं।

विचारधारात्मक मसलों पर '95–'98 के विजातीय रुझानों को सामान्य–परिषद द्वारा और आगे बढ़ाया जा चुका है। इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। विचारधारात्मक सवालों पर का.रामनाथ की स्वच्छंद बुद्धिजीवी मार्का कार्यशैली की वजह से एक निकाय के तौर पर सामान्य परिषद में विचारधारात्मक–राजनीतिक विभ्रम का कुहासा गहराता गया है।

संगठन के कम्युनिस्ट रूपांतरण को केन्द्रीय चुनौती मानने के बावजूद अपनी आत्मोद्धार, आत्मोत्थान की गैर–मार्क्सवादी चिंतन पद्धति की वजह से '98 के बाद से आज तक सामान्य–परिषद के स्थान पर पेशेवर कार्यकर्ताओं की कमेटी का गठन तक नहीं किया जा सका है। इतना ही नहीं सामान्य–परिषद में भी स्थायित्व का अभाव बना रहा है। 1998 के बाद से ही सामान्य–परिषद के कई सदस्य अपनी भूमिकाओं से पीछे हटकर सहानुभूतिकर्ताओं की भूमिका में आ चुके हैं। कुछ इंकलाब की जिम्मेदारियों से पूरी तरह किनाराकशी कर चुके हैं और कुछ अन्य पार्टी–संगठन में शामिल हो चुके हैं। कुल मिलाकर व्यक्ति केंद्रित,

भाववादी विश्लेषण पद्धति पूरे संगठन का रूपांतरण तो दूर, कुछ कार्यकर्ताओं का रूपांतरण कर, एक 'स्थायी कोर' तक के निर्माण में बाधा बनी हुई है।

समाजवादी क्रांति की रणनीतिक लाइन की अपनी समझ को और ज्यादा परिपक्व बनाकर विकसित करते हुए आंदोलन में बहस संचालित करना तो दूर 'सामान्य–परिषद' खुद ही लाइन के सवाल पर नहीं टिकी रह सकी। इसके कई सदस्य कालांतर में नव जनवादी क्रांति के झंडाबरदार हो गए और पूर्व में केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के भी सदस्य रहे एक सज्जन त्रात्स्कीपंथी हो गये। जाहिर है, इसका कारण का. रामनाथ द्वारा रणनीतिक लाइन के मसले पर बे सिर–पैर की हवाई बातें करने के साथ–साथ यह भी था कि '97–'98 में राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के ताजा मूल्यांकन की रोशनी में ही मौजूदा विवाद के समाधान की भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले का. रामनाथ और सामान्य परिषद ने 2004 तक भी राष्ट्रीय–अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के मुद्दे पर दस्तावेज तो दूर कोई लेख तक जारी नहीं किया। न ही 1987 के मूल्यांकन की विसंगतियों को दूर करने का लेशमात्र भी प्रयास किया। इस मामले में का.रामनाथ अभी भी शरशय्या पर पड़े उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके अर्जुन मैदान छोड़कर भाग रहे हैं या फिर उनके गुप्त कौशल से भयभीत अपनी विद्या भूल चुके हैं।

सांगठनिक लाइन विकसित करने की चुनौती को ठंडे बस्ते में डाल चुके का.रामनाथ व सामान्य परिषद ने अपनी तदर्थतावाद की कार्यशैली का बिंदास परिचय देते हुए, 1998 की फूट को अंजाम देने के फौरन बाद ही उस समय के एकमात्र अनौपचारिक जनसंगठन को भी भंग कर दिया। इसी तरह एकमात्र औपचारिक छात्र संगठन को भी तदर्थतावाद की बलि चढ़ा दिया गया। कालांतर में सामान्य परिषद ने पुनः एक अनौपचारिक जन मंच की घोषणा कर, 'क्या करें, क्या न करें, ये कैसी मुश्किल हाय' गाते हुए कभी मजदूरों, कभी किसानों, कभी नौजवानों के बीच अपना तंबू गाड़ना–उखाड़ना जारी रखा हुआ है; वहीं दूसरी ओर बगैर आदर्श कोर के औपचारिक जन–संगठन की नींव का पत्थर भी न रखने का दावा करने के बावजूद बगैर कोर व सम्मेलन के नारी संगठन का निर्माण किया। कुल मिलाकर, पानी के बाहर रहकर ही तैराकी सीखकर जनता के समुद्र में कूदने की समझ रखने वाले सामान्य–परिषद के सदस्य किनारे पर ही हथेली मल रहे हैं।

1997 की 'राजनीतिक–सांगठनिक रिपोर्ट' में जिस विश्लेषण पद्धति को अख्तियार करते हुए जल्द ही पूरे पार्टी–संगठन के कम्युनिस्ट रूपांतरण के दावे किये जा रहे थे उसका कुल नतीजा यही है कि छात्र संगठन, नारी मोर्चा, प्रकाशन के स्तर पर 'कोई छलांग ;इतमां जीतवनहीद्ध नहीं' की बात आज भी जारी है।

1997 में बुनियादी वर्गों के बीच सम्मेलन से सीधे जाने की बात करने वाले केन्द्रीय संगठनकर्ता कमेटी के सदस्य आज भी मध्यवर्ती संगठनों के जरिये वहां जाने का पूर्वाधार बनाने की ही कदमताल कर रहे हैं।

का. रामनाथ के नेतृत्व में आज भारत की कम्युनिस्ट लीग (माले) (सामान्य परिषद) शेष आन्दोलन से विच्छिन्न एक 'मार्क्सवादी' मठ में तब्दील होती जा रही है जो न तो अपनी बदली हुयी विचारधारात्मक, राजनीतिक, अवस्थितियों को सीधे लिखित तौर पर अपने कार्यकर्ताओं और शेष आन्दोलन

में रखने का साहस जुटा पा रही है, न ही बुनियादी वर्गों के बीच सीधे जाने का। न ही विभिन्न वर्गों–तबकों के औपचारिक संगठनों का निर्माण करके आम जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित कर पा रही है, न ही लगातार असफलताओं के बावजूद 'पार्टी निर्माण' की अपनी गैर मार्क्सवादी समझ का ही सार–संकलन करने का साहस जुटा पा रही है।

कुल मिलाकर, भारत की कम्युनिस्ट लीग (माले), (सामान्य परिषद) उससे कहीं पीछे गई है जहां वह 1997 में खड़ी थी। 1998 में तत्कालीन पार्टी संगठन में फूट डालने के बाद यह लगातार विघटन का शिकार रही है। शीर्ष निकाय से लेकर नीचे तक इसके कार्यकर्ता समय–समय पर इसका साथ छोड़ते रहे हैं। यह सिलसिला अभी तक अनवरत जारी है।

लगातार विघटन से त्रस्त यह संगठन कम्युनिस्ट रूपान्तरण के नाम पर जो कुछ कर रहा है वह कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा और कुंठा को ही जन्म दे रहा है जिसके परिणामस्वरूप विघटन को और बढ़ावा मिलता है।

कम्युनिस्ट रूपान्तरण की इसकी आध्यात्मिक लाइन का यह नतीजा हुआ कि इस संगठन ने इंकलाब की सभी चुनौतियों से अपना नाता तोड़ लिया है और यह स्थिति इसे परेशान न करे, इसके लिए इसने आपने आप को एक खोल में बन्द कर लिया है। बाहरी कष्टप्रद दुनिया के थपेड़ों से दूर एकान्तवासी मठ के निर्माण में काफी दूर तक प्रगति की जा चुकी है।

आज यह साफ है कि सामान्य परिषद की इस परिणति की जड़ें उस लाइन में है जिस पर का. रामनाथ एक लम्बे समय से, कमोबेश भारत की कम्युनिस्ट लीग (माले) की स्थापना के साथ से ही चलते रहे हैं। फर्क केवल यह है कि उनकी लाइन आज अपनी तार्किक परिणति तक पहुंच रही है।

इस लाइन के चार मुख्य बिन्दु हैं : (1) बुनियादी वर्गों में पार्टी संगठन के काम को केन्द्रित करने से इस या उस बहाने बचना। (II) अनऔपचारिक स्वेच्छाचारी सांगठनिक कार्यशैली, (III) व्यक्तिवादी विश्लेषण पद्धति, (IV) अंतः पार्टी मतभेदों के पैदा होने पर राजनीति को नहीं बल्कि संगठन को कमान में रखना तथा विरोधी पक्ष को अलगाव में डालने की कोशिश करना।

आज समूचा सी.एल.आई. का खेमा और खासकर सामान्य परिषद का. रामनाथ की इस लाइन की कीमत चुका रहा है। इसने पहले ही भारत के क्रांतिकारी आन्दोलन को काफी नुकसान पहुंचाया है। यदि सामान्य परिषद इस लाइन से अपने आप को मुक्त नहीं करती तो उसका अंततः उससे बुरा हश्र होगा जितना आज इसका कोई भी सदस्य कल्पना नहीं कर सकता है। साथियो, पहले ही बहुत देर हो चुकी है।

□ □ □